International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बिहार के भोजपुर जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की उच्च शिक्षा की स्थिति

विजेता कुमारी[1], डॉ. विजय कुमार गुप्ता[2]

[1,2]शिक्षा विभाग, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड

सारांश (Abstract)

उच्च शिक्षा सामाजिक गतिशीलता, मानव क्षमता, रोजगार-संबंधी अवसरों और सामाजिक न्याय के विस्तार का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसके बावजूद ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुँच, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, शैक्षिक निरंतरता और संस्थागत सुविधाओं के वितरण में असमानताएँ दिखाई देती हैं। प्रस्तुत शोध-आलेख बिहार के भोजपुर जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की उच्च शिक्षा की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन विजेता कुमारी के पीएच.डी. शोध-प्रबंध में उपलब्ध **460 उत्तरदाताओं** के विश्लेषण पर आधारित है, जिनमें 240 ग्रामीण तथा 220 शहरी उत्तरदाता सम्मिलित हैं।अध्ययन में प्रश्नावली, साक्षात्कार, अभिलेखीय स्रोतों तथा शोध-प्रबंध में वर्णित वर्णनात्मक एवं अनुमानात्मक सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया है। उत्तरदाताओं में महिलाओं की भागीदारी 55 प्रतिशत तथा पुरुषों की 45 प्रतिशत रही। सर्वाधिक आयु-वर्ग 21–24 वर्ष का था, जिसमें 45.7 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित थे। ग्रामीण क्षेत्रों के 42.1 प्रतिशत उत्तरदाता ₹10,000 से कम मासिक पारिवारिक आय-समूह में थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 27.3 प्रतिशत था। अध्ययन में उल्लिखित आय-आधारित ग्रामीण एवं शहरी अंतर उच्च शिक्षा तक पहुँच में आर्थिक संसाधनों की भूमिका को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

शोध-प्रबंध की अलग-अलग तालिकाओं में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio—GER) के लिए विभिन्न आधार एवं मापन प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए इस शोध-आलेख में उत्तरदाता-आधारित वितरण, अध्ययन-प्रस्तुत GER तथा संस्थान-आधारित संकेतकों को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केवल उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक सहायता, परिवहन सुविधाएँ, शैक्षिक गुणवत्ता तथा सूचना एवं संचार सुविधाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी असमानताओं को कम करने के लिए समावेशी शैक्षिक नीतियों, छात्रवृत्ति योजनाओं, आधारभूत संरचना के विकास तथा सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

प्रमुख शब्द: उच्च शिक्षा, ग्रामीण–शहरी असमानता, भोजपुर जिला, शैक्षिक सहभागिता, सकल नामांकन अनुपात, सामाजिक समावेशन।

प्रस्तावना

शिक्षा सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के साथ-साथ व्यक्ति की निर्णय क्षमता, आजीविका के अवसरों तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रभावित करती है। उच्च शिक्षा इस प्रक्रिया का अपेक्षाकृत विशिष्ट चरण है, क्योंकि इसमें प्रवेश के लिए पूर्व शिक्षा की उपलब्धता, पारिवारिक आय, सामाजिक समर्थन तथा संस्थागत संसाधनों की

आवश्यकता होती है।ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में इन संसाधनों तक समान रूप से पहुँच प्राप्त नहीं हो पाती। जहाँ शहरी क्षेत्रों में महाविद्यालय, पुस्तकालय, परिवहन और सूचना-संचार सुविधाओं की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता हो सकती है, वहीं ग्रामीण विद्यार्थियों को लंबी दूरी, परिवहन की कठिनाइयों, आर्थिक उत्तरदायित्वों तथा शैक्षिक सहायता की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बिहार के भोजपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में इस असमानता का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। जिले में उपलब्ध उच्च शिक्षण संस्थान, पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियाँ, विद्यार्थियों की सहभागिता, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा शैक्षिक निरंतरता जैसे कारक उच्च शिक्षा की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करते हैं।इन कारकों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक परिस्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केवल नामांकन संबंधी अंतर को स्पष्ट करना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को समझना भी है जो विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में प्रवेश, निरंतर अध्ययन तथा शैक्षिक अवसरों के उपयोग को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत शोध-आलेख भोजपुर जिले में उच्च शिक्षा की ग्रामीण–शहरी असमानता को सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करता है। साथ ही, यह अध्ययन उच्च शिक्षा की समान उपलब्धता, शैक्षिक न्याय तथा समावेशी विकास से संबंधित नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

उच्च शिक्षा की अवधारणा एवं पूर्ववर्ती अध्ययन

उच्च शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य मान्य उत्तर-माध्यमिक अध्ययन-क्रम सम्मिलित होते हैं। इस शिक्षा प्रणाली को ऐसा स्तर माना जाता है जहाँ विशिष्ट विषय-ज्ञान, आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान और पेशेवर दक्षता विकसित होती है। उच्च शिक्षा में समानता का अर्थ केवल प्रवेश-द्वार खोल देना नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और लैंगिक बाधाओं के बीच शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करना भी है। समान अवसर तथा समान परिणाम अलग अवधारणाएँ हैं; इसलिए किसी समूह के नामांकन की मात्रा पर उसके पीछे संसाधन, परिवेश और सामाजिक कारकों की जाँच अपेक्षित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में व्यापक भागीदारी, बहुविषयक शिक्षा, समानता और गुणवत्तापूर्ण अधिगम को महत्त्व देती है। यह नीति नए प्रभावी महाविद्यालयों की क्षमता, शिक्षा की उपलब्धता, डिजिटल संसाधनों और विद्यार्थी सहायता पर निर्भर करती है। भोजपुर जैसे जिले में नीतिगत सिद्धांतों को क्षेत्रीय अनुभवों से जोड़कर समझना अधिक उपयोगी है।

सैद्धांतिक साहित्य एवं विचार की पृष्ठभूमि में सेन (1999) के क्षमता दृष्टिकोण में शिक्षा व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार का साधन है। इस दृष्टिकोण से नामांकन ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन-विकल्प बढ़ना भी असर है।

बुर्दियू (1986) की सामाजिक और सांस्कृतिक पूँजी संबंधी प्रतिपादन समझाता है कि परिवार में उपलब्ध सूचना, भाषा-संपर्क, शैक्षिक मार्गदर्शन तथा सामाजिक नेटवर्क उच्च शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक पूँजी के साथ सांस्कृतिक पूँजी का अभाव ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए चुनौती के समान करता है।

तिलक (Tilak, 2021) ने अपने अध्ययन में उच्च शिक्षा पर आर्थिक असमानता के प्रभाव का विश्लेषण किया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSSO) के आँकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि उच्च आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में सहभागिता अधिक होती है, जबकि निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करता है।

सी.पी.आर.एच.ई.–एन.आई.ई.पी.ए. (CPRHE-NIEPA, 2020) के अध्ययन में बिहार के चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों का विश्लेषण किया गया। इसमें भोजपुर जिले के जगजीवन कॉलेज तथा वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

का उल्लेख मिलता है। शोध-प्रबंध के अनुसार अध्ययन में सामाजिक विविधता, भेदभाव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सहभागिता तथा महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं को रेखांकित किया गया।

शोध भूमि पत्रिका (2024) में भोजपुर जिले के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित अध्ययन का उल्लेख मिलता है। इसमें जातिगत भेदभाव तथा आर्थिक संसाधनों की कमी को शैक्षिक प्रगति में बाधक बताया गया है। अध्ययन उच्च शिक्षा में सामाजिक समानता तथा वंचित वर्गों की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO, 2017–18) के 75वें दौर के आँकड़ों का उपयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सहभागिता तथा आर्थिक असमानताओं के अध्ययन के लिए किया गया है। इसमें पारिवारिक आय और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को उच्च शिक्षा तक पहुँच से संबंधित महत्त्वपूर्ण कारकों के रूप में देखा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में उच्च शिक्षा की उपलब्धता, समान अवसर, बहुविषयक शिक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया गया है। नीति में उच्च शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने, डिजिटल संसाधनों के विस्तार तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शैक्षिक अवसर विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE, 2021–22) में उच्च शिक्षा संस्थानों, विद्यार्थियों के नामांकन तथा सकल नामांकन अनुपात से संबंधित आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन आँकड़ों का उपयोग उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं तथा महिला एवं पुरुष विद्यार्थियों की सहभागिता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

शोध समस्या का कथन

भोजपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की स्थिति किन आयामों में भिन्न है, तथा जनसांख्यिकीय और आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ यह भिन्नता कैसे जुड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्रामीण–शहरी सहभागिता, आय, लिंग, सामाजिक समूह, आयु, शिक्षा स्तर और संसाधन अवसर का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। अध्ययन का औचित्य क्षेत्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा की असमानता को पहचानना और योजना के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाना है। यदि केवल जिले के औसत देखे जाएँ, तो ग्रामीण विद्यार्थियों की विशिष्ट कठिनाइयाँ छिप सकती हैं। इस प्रकार केवल ग्रामीण और शहरी नामांकन की तुलना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आय तथा सामाजिक समूह की संरचना भी अलग हो सकती है। प्रस्तुत लेख इन कारकों को साथ पढ़ने का प्रयास करता है और निष्कर्ष को नीतिगत चर्चा से जोड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भोजपुर जिले में ग्रामीण एवं शहरी उत्तरदाताओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय संरचना की तुलना करना।
2. शिक्षा स्तर, आय एवं लिंग के आधार पर उच्च शिक्षा में सहभागिता के पैटर्न को समझना।
3. आय और सामाजिक समूह के साथ क्षेत्रीय शैक्षिक अंतर के संबंधों का विश्लेषण करना।
4. शोध-प्रबंध में उल्लिखित नामांकन एवं संसाधन-सूचकों का क्षेत्रीय व्याख्या करना।
5. ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अवसर-समानता बढ़ाने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाएँ

H_{01}: ग्रामीण एवं शहरी उत्तरदाताओं के लिंग-वितरण में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक संबंध नहीं है।

H_{02}: ग्रामीण एवं शहरी उत्तरदाताओं की आय-संरचना तथा आय-वितरण में कोई सार्थक क्षेत्रीय अंतर नहीं है।

H_{03}: अध्ययन में प्रस्तुत ग्रामीण और शहरी उच्च शिक्षा नामांकन संकेतकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध-विधि एवं

प्रस्तुत शोध-आलेख वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध-रचना पर आधारित द्वितीयक विश्लेषण है। शोध-प्रबंध के अध्याय 4 में विश्लेषित **कुल 460 उत्तरदाताओं** को यहाँ अंतिम विश्लेषणात्मक नमूना माना गया है। इनमें ग्रामीण 240 (52.2%) तथा शहरी 220 (47.8%) हैं। लेख में 500 के प्रारंभिक चयन-आँकड़े को अंतिम विश्लेषणात्मक नमूना नहीं माना गया है। शोध-प्रबंध में प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा सांख्यिकीय विवरण और SPSS-आधारित सांख्यिकीय प्रविधियों का उल्लेख मिलता है। प्रस्तुत लेख में मूल उत्तरदाता-स्तरीय डेटा उपलब्ध होने के कारण परीक्षणों की पुनर्गणना की गई; शोध-प्रबंध में प्रकाशित परिणाम जहाँ प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें उसी स्रोत के परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1 : अध्ययन में अंतिम विश्लेषणात्मक नमूने का वितरण

क्षेत्र	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	240	52.2
शहरी	220	47.8
कुल	**460**	**100.0**

तालिका 1 पुष्टि करती है कि क्षेत्रीय वितरण तुलनात्मक अध्ययन के लिए पर्याप्त रूप से संतुलित है। फिर भी नमूने की संरचना पूरे भोजपुर जिले के सभी समूहों का प्रतिनिधित्व प्रमाणित करती। इसलिए निष्कर्षों के सामान्यीकरण में चयन-विधि और सर्वेक्षण-परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रयुक्त विश्लेषण के रूपरेखा के पहले चरण में आवृत्ति और प्रतिशत से उत्तरदाताओं की संरचना समझी गई। दूसरे चरण में ग्रामीण–शहरी अनुपात की तुलना की गई। तीसरे चरण में थीसिस में उल्लिखित χ^2-परीक्षण, t-परीक्षण तथा ANOVA के परिणामों को संदर्भ लिया गया। परिणामों की व्याख्या में जहाँ कुछ संकेतक अलग आधार पर उपलब्ध हैं, उन्हें एक-दूसरे में मिलाकर संयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाला गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

उत्तरदाताओं का लिंग एवं आय वितरण

कुल 460 उत्तरदाताओं में 207 पुरुष (45.0%) और 253 महिलाएँ (55.0%) थीं। ग्रामीण समूह में महिलाओं की हिस्सेदारी 51.7%, जबकि शहरी समूह में 58.6% थी। महिला उत्तरदाताओं की अधिक उपस्थिति को सर्वेक्षण में उनकी सहभागिता का संकेत माना जाता है; इसे जिले के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला नामांकन की दर के बराबर लिया गया। । शोध-प्रबंध में लिंग और क्षेत्र के संबंध के लिए $\chi^2 = 2.34$ तथा $p = 0.12$ दिया गया है, जिसके आधार पर 5% स्तर पर सांख्यिकीय सार्थकता स्थापित नहीं होती।

उत्तरदाताओं का लिंग एवं आयु वितरण

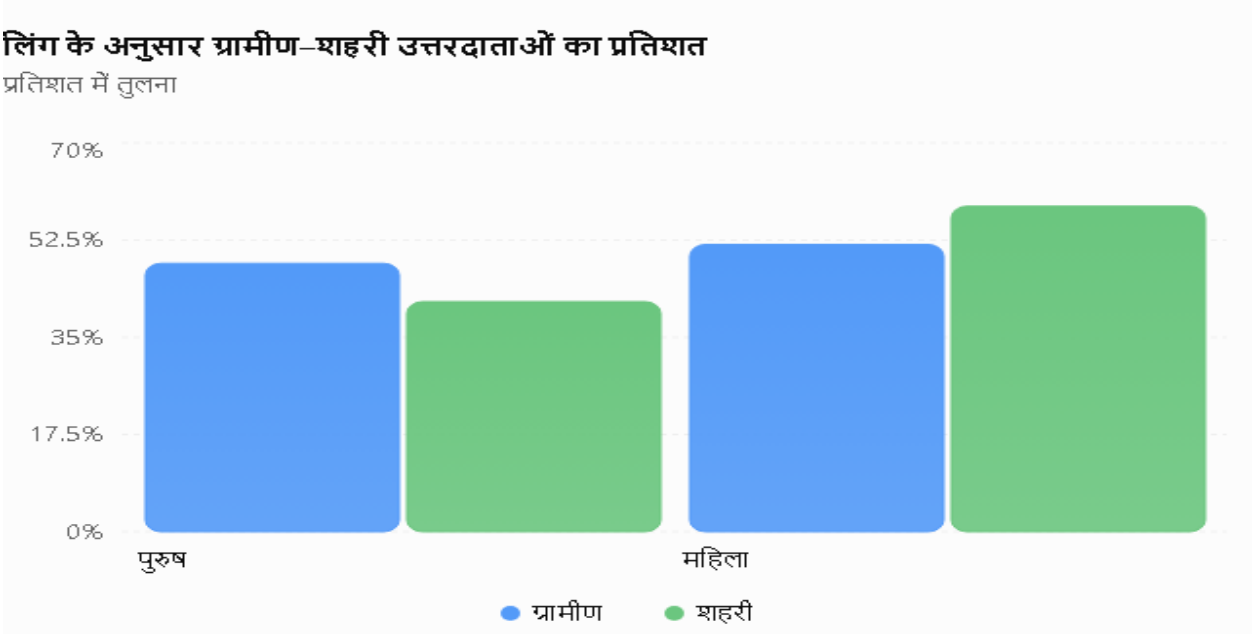
कुल 460 उत्तरदाताओं में 207 पुरुष (45.0%) और 253 महिलाएँ (55.0%) थीं। ग्रामीण समूह में महिलाओं की हिस्सेदारी 51.7%, जबकि शहरी समूह में 58.6% थी। महिला उत्तरदाताओं की अधिक उपस्थिति को सर्वेक्षण में उनकी सहभागिता का संकेत माना जा सकता है इसे जिले के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला नामांकन की दर के बराबर नहीं समझना चाहिए। शोध-प्रबंध में लिंग और क्षेत्र के संबंध के लिए $\chi^2 = 2.34$ तथा $p = 0.12$ दिया गया है, जिसके आधार पर 5% स्तर पर सांख्यिकीय सार्थकता स्थापित नहीं होती।

दण्ड आरेख – : ग्रामीण एवं शहरी उत्तरदाताओं का लिंगानुसार वितरण
लिंग के अनुसार ग्रामीण–शहरी उत्तरदाताओं का प्रतिशत में तुलना

तालिका 2 : लिंग के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

लिंग	कुल संख्या	कुल %	ग्रामीण %	शहरी %
पुरुष	207	45.0	48.3	41.4
महिला	253	55.0	51.7	58.6
कुल	**460**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

आयु-वर्ग के संदर्भ में 17–20 वर्ष के 185 (40.2%), 21–24 वर्ष के 210 (45.7%) और 25 वर्ष अथवा अधिक आयु के 65 (14.1%) उत्तरदाता थे। ग्रामीण समूह में 17–20 वर्ष की हिस्सेदारी 45.0% तथा शहरी समूह में 35.0% रही। दूसरी ओर 21–24 वर्ष की हिस्सेदारी ग्रामीण 42.5% तथा शहरी 49.1% रही। इन आँकड़ों में आयु-संरचना का क्षेत्रीय अंतर दिखाई देता है, परंतु केवल आयु अनुपात के आधार पर प्रवेश, पढ़ाई छोड़ने या डिग्री पूर्ण करने की दर निर्धारित नहीं की जाती।



व्याख्या: दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष उत्तरदाताओं का प्रतिशत 48.3% तथा महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत 51.7% है। शहरी क्षेत्र में पुरुष उत्तरदाताओं का प्रतिशत 41.4% तथा महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत 58.6% है।

तालिका 3 : आयु-वर्ग के अनुसार ग्रामीण–शहरी वितरण

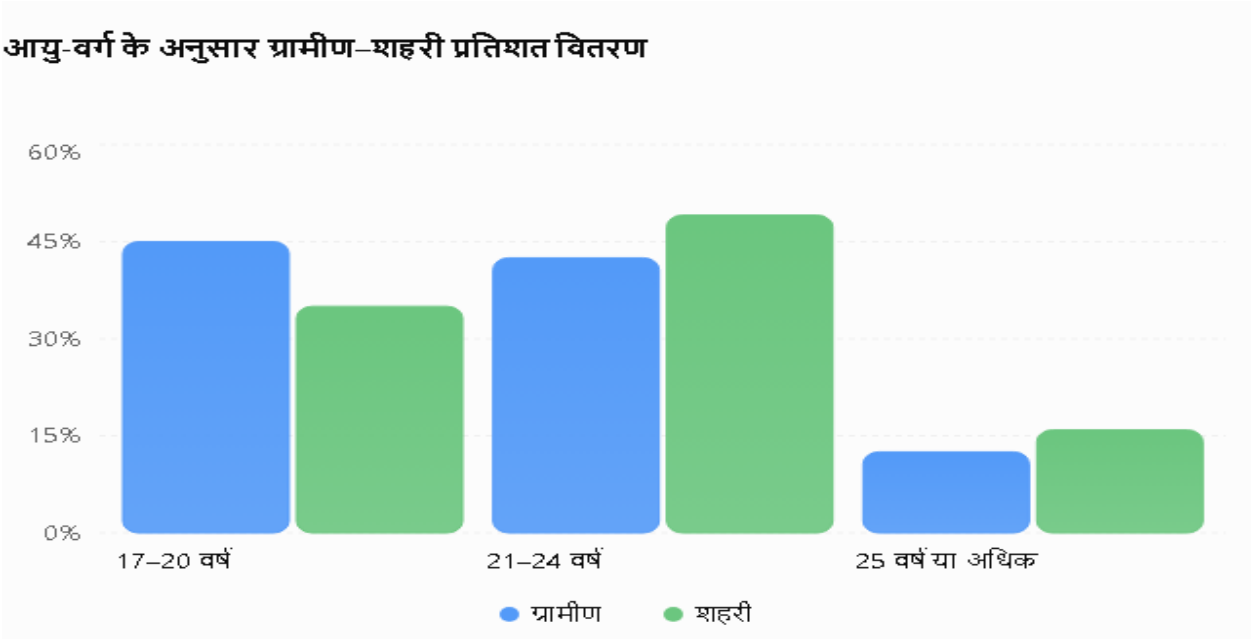
आयु (वर्ष)	कुल संख्या	कुल %	ग्रामीण %	शहरी %
17–20	185	40.2	45.0	35.0
21–24	210	45.7	42.5	49.1
25 या अधिक	65	14.1	12.5	15.9

कुल	**460**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

अध्ययन में औसत आयु ग्रामीण 21.2 और शहरी 22.8 वर्ष दी गई है। शोध-प्रबंध के अनुसार यह अंतर $t = 4.21$, $df = 458$, $p < 0.001$ पर सार्थक पाया गया है। इस परिणाम की उपयोगिता यह है कि तुलनात्मक विश्लेषण करते समय आयु को नियंत्रित कारक के रूप में देखना चाहिए। उदाहरणतः शहरी नमूने में उच्च आयु समूह की अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी स्नातकोत्तर स्तर की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करती है।

दण्ड आरेख – 2 : आयु-वर्ग के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी उत्तरदाताओं का वितरण

आयु-वर्ग के अनुसार ग्रामीण–शहरी प्रतिशत वितरण



व्याख्या: दण्ड आरेख के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 17–20 वर्ष आयु-वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक 45.0% है, जबकि शहरी क्षेत्र में 21–24 वर्ष आयु-वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक 49.1% है। इससे ग्रामीण एवं शहरी उत्तरदाताओं की आयु-संरचना में अंतर दिखाई देता है।

शिक्षा स्तर की स्थिति

कुल नमूने में +2 स्तर के 150 (32.6%), स्नातक के 230 (50.0%) तथा स्नातकोत्तर के 80 (17.4%) उत्तरदाता थे। ग्रामीण क्षेत्र में +2 स्तर का अनुपात 38.3% और शहरी क्षेत्र में 26.4% दर्ज हुआ। शहरी समूह में स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तरदाताओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक मिला। अध्ययन में शिक्षा स्तर और क्षेत्र के संबंध के लिए $p = 0.03$ का उल्लेख है। +2 श्रेणी को यहाँ विश्लेषण में प्रयुक्त शिक्षा-स्तर श्रेणी के रूप में रखा गया है; इसे उच्च शिक्षा के औपचारिक GER की गणना में स्वतः सम्मिलित नहीं माना गया है।

आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि की तुलना

पारिवारिक आय उच्च शिक्षा तक पहुँच के प्रमुख साधनों में से एक है। यात्रा, आवास, पुस्तकें, इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पढ़ाई के साथ श्रम करने की आवश्यकता भी आय से जुड़ी होती है। शोध-प्रबंध में

₹10,000 से कम मासिक आय वाले उत्तरदाताओं की कुल हिस्सेदारी 35% है, जबकि ग्रामीण समूह में यह 42.1% और शहरी समूह में 27.3% है। ₹30,000 से अधिक आय समूह में ग्रामीण 19.6% तथा शहरी 30.5% हैं। इससे अध्ययन-नमूने में ग्रामीण निम्न-आय समूह की अधिक उपस्थिति पुष्ट होती है।

तालिका 4 : मासिक पारिवारिक आय की क्षेत्रीय तुलना

मासिक आय	कुल संख्या	कुल %	ग्रामीण %	शहरी %
₹10,000 से कम	161	35.0	42.1	27.3
₹10,001–30,000	184	40.0	38.3	42.3
₹30,000 से अधिक	115	25.0	19.6	30.5

इस समूह में आय-संबंधी क्षेत्रीय अंतर के लिए $F = 18.76$, $p < 0.001$ अंकित है। चूँकि मूल डेटा तथा ANOVA के पूर्ण मॉडल-विवरण यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए परीक्षण के स्वतंत्र सत्यापित निष्कर्ष की तरह प्रस्तुत करने के बजाय शोध-प्रबंध में प्रतिवेदित परिणाम माना जाना चाहिए। वर्णनात्मक अंतर फिर भी स्पष्ट है: शहरी समूह में उच्च-आय परिवारों का अनुपात अधिक और ग्रामीण समूह में निम्न-आय परिवारों का अनुपात अधिक है।

सामाजिक समूह एवं समावेशन

नमूने में सामान्य समूह के 138 (30%), अन्य पिछड़ा समूह के 184 (40%) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति समूह के 138 (30%) उत्तरदाता हैं। ग्रामीण समूह में OBC की हिस्सेदारी 42.5% और SC/ST की 32.5%, जबकि शहरी समूह में क्रमशः 37.3% और 27.3% रही। इस वितरण का आशय यह है कि नमूना सामाजिक रूप से विविध है, लेकिन सर्वेक्षण में किसी समूह की हिस्सेदारी को जिले की उस समूह की उच्च शिक्षा उपलब्धि के बराबर नहीं माना जा सकता। समूहों की तुलना करते हुए प्रवेश-सुविधा, पारिवारिक आर्थिक दशा तथा संस्थागत सहायता भी देखना आवश्यक है।

तालिका 5 : सामाजिक समूह के अनुसार वितरण

समूह	कुल संख्या	कुल %	ग्रामीण %	शहरी %
सामान्य	138	30.0	25.0	35.5
OBC	184	40.0	42.5	37.3
SC/ST	138	30.0	32.5	27.3

इन आँकड़ों से पता चलता है कि दोनों क्षेत्रों की सामाजिक रूप से विविध संरचना है। समावेशी नीतिगत चर्चा में समान रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए सहायता की व्यवस्था के साथ विशेष वंचित समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वेक्षण में समूहों का अनुपात और शिक्षा में उन समूहों का सकल नामांकन अनुपात अलग माप हैं; इन्हें आपस में प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

नामांकन संकेतक एवं संस्थागत संसाधन

शोध-प्रबंध के खंड 4.2 में आयु-आधारित नामांकन (GER) संकेतक दिए गए हैं। उस खंड में 17–20 वर्ष समूह के

लिए ग्रामीण 15.2% और शहरी 28.4%, 21–24 वर्ष समूह के लिए ग्रामीण 18.6% और शहरी 32.1%, तथा 25 वर्ष एवं अधिक समूह के लिए ग्रामीण 8.9% और शहरी 16.7% अंकित हैं। इन तीनों तुलना-बिंदुओं पर शहरी मान अधिक हैं। तथापि सामान्यतः उच्च शिक्षा का आधिकारिक GER विशिष्ट आयु-समूह तथा जनसंख्या-आधारित हर (denominator) से निर्धारित होता है। इसलिए शोध-प्रबंध में प्रस्तुत आयु-वार संकेतकों को बिना मूल गणना-पत्रक के आधिकारिक जिला GER नहीं माना जा सकता।

तालिका 6 : शोध-प्रबंध में प्रतिवेदित आयु-आधारित नामांकन संकेतक

आयु-वर्ग	ग्रामीण %	शहरी %	अंतर (प्रतिशत अंक)
17–20 वर्ष	15.2	28.4	13.2
21–24 वर्ष	18.6	32.1	13.5
25 वर्ष एवं अधिक	8.9	16.7	7.8

यह अंतर शहरी प्रतिशत में से ग्रामीण प्रतिशत घटाकर निकाला गया है; यह स्वतंत्र सर्वेक्षण से प्राप्त नई माप नहीं है।

थीसिस के अन्य उपखंडों में समग्र GER तथा समूह-आधारित GER के अलग स्तर और संदर्भ भी उपलब्ध हैं। इसलिए इन सभी मानों को एक ही परिभाषा या एक ही औसत से जिला-स्तरीय GER बताना उपयुक्त नहीं होगा। लेख का मुख्य परिणाम सर्वेक्षण में पहचानी गई सुविधाओं की क्षेत्रीय विषमता है।

संस्थागत सुविधाओं का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

शोध-प्रबंध के अनुसार अध्ययन में 15 संस्थानों को संसाधन समीक्षा में सम्मिलित किया गया है—8 ग्रामीण और 7 शहरी। इसमें ग्रामीण संस्थानों का औसत नामांकन लगभग 912 तथा शहरी संस्थानों का लगभग 2457 बताया गया है। ग्रामीण संस्थानों के लिए औसत शिक्षक-छात्र अनुपात लगभग 1:49 और शहरी संस्थानों के लिए 1:31 प्रतिवेदित है।ये संस्थान-आधारित अवलोकन 460 उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत सर्वेक्षण से भिन्न विश्लेषण-इकाई रखते हैं। इन्हें मिलाकर एक संयुक्त उत्तरदाता-आधारित आँकड़ा नहीं बनाया गया है।ग्रामीण संस्थानों में अधिक विद्यार्थी-शिक्षक दबाव, परिवहन दूरी तथा सीमित सुविधाएँ अध्ययन की निरंतरता पर प्रभाव डाल सकती हैं। वहीं शहरी संस्थानों में अधिक पुस्तकालय, शैक्षिक संपर्क और सहपाठी नेटवर्क की उपलब्धता उपयोगी हो सकती है। हालाँकि अधिक नामांकन को अधिक गुणवत्ता का प्रमाण नहीं समझा जा सकता; पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पुस्तक-विनिष्पादन तथा छात्र-अनुभव भी स्रोत रूप में मापने चाहिए।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2020)। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।** नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2021–22)। **अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE 2021–22)।** नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
3. सेन, अमर्त्य। (1999)। **विकास के रूप में स्वतंत्रता (Development as Freedom)।** ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. बुर्दियू, पियरे। (1986)। **पूँजी के रूप (The Forms of Capital)।** पुस्तक: *शिक्षा के समाजशास्त्र के लिए सिद्धांत और अनुसंधान की पुस्तिका (Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*

5. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। (2019)। **भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 75वाँ दौर (2017–18)।** रिपोर्ट संख्या 585। नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
6. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2024)। **अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), 2021–22।** उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
7. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2026)। **अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), 2022–23।** उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
8. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2026)। **अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE), 2023–24।** उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
9. यूनेस्को। (2023)। **वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023: शिक्षा में प्रौद्योगिकी—किसकी शर्तों पर एक उपकरण?** पेरिस: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
10. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। (2018)। **भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 75वाँ दौर, जुलाई 2017 से जून 2018।** भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
11. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2024)। **अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021–22 के प्रमुख निष्कर्ष।** पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।